



कृषि अधोसंरचना कोष (AIF)

फार्म गेट आधारभूत अधोसंरचना हेतु कृषि अधोसंरचना कोष की घोषणा की गई है, फार्म गेट एवं समेकन केंद्र (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप आदि) पर कृषि अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

“एआईएफ” की मुख्य विशेषताएँ



सभी प्रकार 3 परिणत परिणर्ष की ध्याड फुट पर हेली। यहा फुट अडिकलन 7 कर्षा की अडिकलन के लिए हेली।



2 करोड रुपए तक के प्रकन के लिए गहन एन लघु उद्यमयोजना हेतु प्रकन करके गिरी संस्था (सीडीटीएनएसडी) के लकन

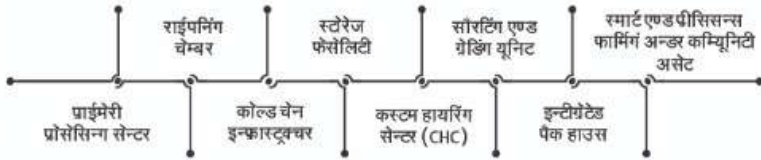


अन्य सरकारी सगिसे योजना एकीक कर कावक भी इन के साथ सं सगते है,



कई सरकारी एन गिजी बैंक सेक्टर को प्राथमिकता प्रकन के लिए

AIF के अंतर्गत प्रास्थापित गतिविधियाँ



कौन आवेदन कर सकता है



व्यक्तिगत

किसान लोकल ब्यापारी, ट्रेडर्स आदि कृषि व्यापारी



संस्थाएँ

स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-व्यवसाय, सार्वजनिक-निजी भागीदारी



सरकारी संस्थान

प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी (PACS), मार्केटिंग को-ऑपरेटिव, एपीएमसी मंडियां



एआईएफ पोर्टल पर रजिस्ट्र कर मोबाइल नंबर, आधार के साथ एवं बैंक के अडिकलन का विवरण दे। www.agriinfra.dac.gov.in



कृषि आगन भी फार्म और सगनिक कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट



आपनी बैंक सगन पुन



कृषि निर्यात ट्रेड कर मेष के सगन से रिपोर्ट



यदि आवेदन सगनपित है तो सगनिक कर, अडिकलन दरसगन ओगनलन बैंक सगन से अडिकलन करे।



अडिकलन सगनपित आगि सगनपित भेग गण सगनपित ओगन सगनपित पर अगुडेट विवरण गण



राज्य नोडल कार्यालय – बीज भवन, (कृषि विभाग), अरेरा हिल्स, भोपाल – 462004

☎ - 0755-4229282

✉ mdpudbeejnigam@gmail.com



योजना के लिए
दिशानिर्देश
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
का
'कृषि अवसंरचना कोष' के तहत वित्तीय सुविधा

योजना के दिशानिर्देश

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग कृषि और किसान
कल्याण विभाग
भारत सरकार

सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं।
1	परिचय	3
2	योजना का औचित्य	3-4
3	योजना के उद्देश्य	4-5
4	योजना का कार्यान्वयन काल	5
5	सरकारी बजट सहायता	5-6
6	योग्य परियोजनाएँ	6-7
7	वित्तपोषण सुविधा और पात्र लाभार्थियों का आकार	7
8	भाग लेने वाली संस्थाएँ	7
9	पुनर्वित्त	7
10	उधार दर पर केंप	7-8
11	परियोजना प्रबंधन और हैंडहोल्डिंग समर्थन	8
12	कन्वर्जेंस	8
13	योजना का पुनरीक्षण	8
14	निगरानी ढांचा	9
15	आउटपुट और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF)	9
16	पीएफएमएस के साथ संबंध	9
17	पात्र उधारकर्ता के चयन के लिए मानदंड	9
18	वीजीएफ की आवश्यकता	9
19	सेक्टर विशिष्ट फोकस	9
20	राज्यों पर विशेष ध्यान दें	10

कृषि अधोसंरचना कोष 'के तहत वित्तपोषण सुविधा के केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए योजना दिशा निर्देश

1 परिचय

कृषि विकास और उत्पादन की गतिशीलता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से हो, विशेष रूप से फसल के बाद के चरण में किसानों के लिए मूल्यवर्धन और उचित सौदे के अवसर के लिए उपज का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के बुनियादी ढांचे का विकास प्रकृति की अनिश्चितताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति आदि समस्याओं का समाधान करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, माननीय वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कृषि अधोसंरचना लिए दिनांक 15.05.2020 1.00 लाख करोड़ रूपय के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। फार्म-गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप आदि) में कृषि अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदु, सस्ती और आर्थिक रूप से सक्षम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उक्त राशि से वित्त पोषण होगा।

तदनुसार, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की है जो फसल प्रबंधन के लिए एक मध्यम - दीर्घकालिक ऋण, सुविधा तथा विभिन्न प्रोजेक्टों में फसल कटाई उपरांत अधोसंरचनाओं के प्रबंधन एवं समुदायिक कृषि संसाधनों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहयोग एवं वित्तपोषण उपलब्ध करायेगी।

2 योजना का तार्किक विश्लेषण

कृषि एवं उनसे संबद्ध अन्य कार्यों से भारत की कुल जनसंख्या के ~ 58% लोगो के लिए प्राथमिक आय स्रोत हैं। ~ 85% किसान छोटे जोत वाले किसान (SHF) हैं जिनकी खेती की भूमि 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और वे ~ 45% कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। अधिकांश किसानों की वार्षिक आय बहुत कम है। इसके अलावा, भारत में किसानों को बाजारों से जोड़ने के लिए सीमित बुनियादी ढांचा है और इसलिए, 15-20% उपज बर्बाद हो जाती है, जो अपेक्षाकृत अधिक है अन्य देशों में जहां यह 5-15% के बीच होता है। भारत में कृषि में निवेश पिछले 5 वर्षों में 2% से कम सीएजीआर के साथ स्थिर रहा है। वित्त वर्ष 17 में निवेश ~ 2.19 लाख करोड़ था जिसमें से निजी क्षेत्र का हिस्सा था ~ 83% इसके विपरीत उच्च निवेश ~ वित्त वर्ष 2014 में 2.50 लाख करोड़ था और निजी क्षेत्र का उच्च शेयर ~ 88% था। इसके अलावा, निवेशकों में विश्वास की कमी के कारण भी निम्नतर जोत अनुपात (वित्त वर्ष 18 में सकल मूल्य संवर्धन का 14%) के विरुद्ध अन्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 18 में सकल मूल्यवर्धन 33% था।

3 योजना के उद्देश्य

फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए सक्षम परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम - दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा को गति देने, देश में कृषि बुनियादी ढांचे तथा सामुदायिक खेती के संसाधनों में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता देना। इस वित्तपोषण सुविधा से कृषि इको-सिस्टम में सभी हितधारकों के लिए कई उद्देश्य पूर्ण होंगे।

a. किसान (एफपीओ, पैक्स, विपणन सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां सहित)

- किसानों की फसलों को सीधे उपभोक्ताओं को बड़े आधार पर बेचने की सुविधा देने के लिए विपणन के बुनियादी ढांचे में सुधार जिससे किसानों को अधिकाधिक मूल्य प्राप्त हो। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा।
- लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश जिससे किसान, फसल उत्पादन के बाद के न्यूनतम नुकसान और न्यूनतम संख्या में बिचौलियों के साथ बाजार में बिक्री कर पाएंगे। यह आगे किसानों को आत्मनिर्भर करेगा और बाजार तक पहुंच में सुधार करेगा।
- आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में पहुँच के साथ, किसान आगे यह तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में फसल को कब बेचा जाए जिससे वस्तु के उत्पादन का वास्तविक दाम मिल सके।
- उत्पादकता में वृद्धि और आदानों की बेहतरी के लिए सामुदायिक खेती के संसाधन तैयार करना जिससे किसानों को काफी बचत होगी।

b. सरकार

- सरकार ब्याज रहित, प्रोत्साहन और ऋण गारंटी के माध्यम से वर्तमान में चल रही परियोजनाओं में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को सीधे ऋण देने के निर्देश देने में सक्षम होगी। यह कृषि में नवाचार और निजी क्षेत्र के निवेश के चक्र की शुरुआत करेगा।
- कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण, सरकार आगे राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय प्रतिशत को कम करने में सक्षम होगी जिससे कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।
- केंद्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं की संरचना करने में सक्षम होंगे।

c. कृषि उद्यमी और स्टार्टअप

- वित्त पोषण के एक समर्पित स्रोत के साथ, उद्यमी नवीन प्रौद्योगिकियों सहित IoT, AI, आदि का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में नवाचार पर जोर देंगे।

- यह प्रतिभागियों को पारिस्थितिक तंत्र में भी जोड़ेगा और , उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग के मार्ग में सुधार करेगा।

d. बैंकिंग इकोसिस्टम

- क्रेडिट गारंटी के साथ, प्रोत्साहन और ब्याज दर के माप उधार देने वाले संस्थाए कम जोखिम के साथ उधार दे सकेंगी। यह योजना उनके ग्राहक आधार और पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करेगी।
- पुर्नवित्त योजना से सहकारी बैंकें और आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगी।

e. उपभोक्ताओं

- कृषि उपज की कटाई के बाद के पारिस्थितिकी तंत्र में अक्षमताओं को कम करने के साथ, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अधिकतम उत्पाद, बेहतर गुणवत्ता एवं मूल्य के साथ बाजार तक पहुंच सकेगा। कुल मिलाकर, कृषि अवसंरचना में वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से निवेश से सभी इको-सिस्टम के सभी प्रतिभागियों को को लाभ होगा।

4 योजना का कार्यान्वयन काल

यह योजना 2020-21 से 2029-30 तक लागू रहेगी। जिसका संवितरण 4 वर्षों में होगा। प्रथम वर्ष में 10,000 करोड़ रु एवं आगामी 03 वर्षों में 30,000 करोड़ रु किया जाएगा। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत वसूली के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष में हो सकेगा।

5 सरकारी बजट सहायता

पीएमयू की प्रशासनिक लागत के साथ-साथ ब्याज की छूट और ऋण गारंटी शुल्क के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्र.	का नाम अंग	मानदंड
1	ब्याज अधीनता (छूट) लागत	इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर रु 2 करोड़ तक की सीमा तक 3% प्रति वर्ष का ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के मामले में भी ब्याज में छूट 2 करोड़ तक ही सीमित होगी। निजी उद्यमियों के लिए इसकी सीमा और प्रतिशत नेशनल प्रोजेक्ट मोनिटरिंग कमेटी द्वारा तय की जाएगी।

2	क्रेडिट गारंटी लागत	इस वित्त पोषण सुविधा के अन्तर्गत पात्र उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध होगी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत 2.00 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के एफ.पी.ओ प्रमोशन स्कीम में एफ.पी.ओ भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
3	पीएमयू की प्रशासन लागत	DACFW के अन्तर्गत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर PM KISAN के राज्य PMU योजना के लिए सहायता प्रदान करेगी। विभिन्न विशेषज्ञ/जानकार साझेदारों की सेवाएं क्लस्टरो के चिन्हांकन, निर्यात क्लस्टरो की पहचान तथा मांग एवं सप्लाई चेन के अंतर तथा सक्षम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के निर्माण में हितधारकों को सहयोग दिया जायेगा।

6 योग्य परियोजनाएँ

योजना मूल्य श्रृंखला के प्रमुख तत्वों को स्थापित करने और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी

(A) पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे:

- (i) ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं
- (ii) गोदामों (भंडार गृह)
- (iii) सायलो
- (iv) पैक हाउस
- (v) परीक्षण प्रयोगशालाएं (Assaying units)
- (vi) छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ
- (vii) वतानुकूलित वाहन व छोटे शीतगृह
- (viii) सामग्री परिवहन वाहन (लाजिस्टिक) यथा ब्रेवरेज व अन्य
- (ix) प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र
- (x) पकने वाली मंडली (फसल पकाने वाले संयंत्र) (चेंबर)

(B) सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं -

- (i) जैविक आदानों का उत्पादन
- (ii) जैव उद्दीपक उत्पादन इकाइयाँ (ऐसी जैविक खेती जिसमें रसायनिक खादों का न्यूनतम उपयोग हो)
- (iii) स्मार्ट और शुद्ध कृषि के लिए बुनियादी ढाँचा।

(iv) निर्यात क्लस्टर सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति शृंखला बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए पहचान की गई परियोजनाएं।

(v) सामुदायिक खेती की संपत्ति या फसल प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए पीपीपी के तहत केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रचारित परियोजनाएं।

7 वित्तपोषण सुविधा और पात्र लाभार्थियों का आकार

बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), और बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, केंद्रीय / राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को 1.00 लाख करोड़ रूप्यक के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

जिन PACS ने अपने संचालन को संभालने के लिए डिजिटलीकरण को अपनाया है, उन्हें इस योजना के तहत वरीयता दी जाएगी।

8 भाग लेने वाली संस्थाएँ

सभी निर्धारित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड से मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर (MoU) करने के बाद, इस वित्तपोषण की सुविधा को प्रदान करने के लिए भाग ले सकते हैं।

9 पुनर्वित्त

यदि आवश्यक हो, तो नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंक और आरआरबी सहित सभी पात्र ऋण संस्थाओं को अपनी नीति के अनुसार आवश्यकता आधारित पुनर्वित्त समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा।

10 उधार दर पर कैप

उधार देने वाली संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श के बाद भाग लेने वाली उधार देने वाली संस्थाओं की उधार दर का निर्णय लिया जाएगा और सभी हितधारकों को प्रेषित किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए उधार देने वाले संस्थान DAC और FW / NABARD के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय तथा नाबार्ड बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से एक MOU हस्ताक्षर करेंगे, इस विचार के साथ कि नाबार्ड ऋण प्रदाय की दरों पर कैप लगाने के लिए समुचित तरीके से निगोशियट करेगा।

11 परियोजना प्रबंधन और हैंडहोल्डिंग समर्थन

जानकारी एवं ऋण स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक प्रतिभागी एवं उधार प्रदायक संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराया जाएगा। एग्री इंफ्रा फंड का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन एमआईएस प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को निधि के तहत ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा। यह प्रणाली

कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की पारदर्शिता, ब्याज की छूट और ऋण गारंटी की पेशकश, न्यूनतम दस्तावेज, तेजी से अनुमोदन प्रक्रिया सहित अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसी लाभ भी प्रदान करेगी। दूसरी ओर ये प्लेटफॉर्म संपूर्ण जिलों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कुल स्वीकृत उधारकर्ताओं एवं राशि, कुल ब्याज छूट प्राप्त कर्ताओं, ऋण राशि की संक्षिप्त जानकारी, भौगोलिक और जनसंख्यिकीय आधार पर ऋण प्राप्त कर्ताओं और प्रोजेक्टों की समीक्षा करने एवं देखने के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध कराएगा। कुल स्वीकृत राशि और उधारकर्ताओं की संख्या, कुल ब्याज का लाभ उठाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पीएमयू, ऋण विवरण सारांश, DACFW के तहत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर PM KISAN के राज्य PMU को योजना के लिए सहायता प्रदान करेगी।

लाभार्थियों और ऋण देने वाली संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय और राज्य पीएमयू द्वारा सांकेतिक इकाई लागत के साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ऐसी परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।

12 अभिसरण - केंद्र / राज्य सरकार की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना के तहत उपलब्ध कोई भी अनुदान या सब्सिडी इस वित्तपोषण सुविधा के तहत परियोजनाओं के लिए ली जा सकती है। पूंजीगत सब्सिडी के मामलों में ऐसी राशि को प्रवर्तक के योगदान के रूप में माना जाएगा। हालांकि, परियोजना की लागत का न्यूनतम 10% प्रमोटर के योगदान के रूप में अनिवार्य होगा।

13 योजना का पुनरीक्षण

20,000 करोड़ रुपये के वितरण पूर्ण होने पर व्यय विभाग द्वारा योजना का पुनरावलोकन किया जाएगा यदि उसका मूल्यांकन एवं योजना परिचालन के मध्य में कोई सुधार आवश्यक हो। जब भी आवश्यक होगा अंत-लाइन मूल्यांकन के अलावा योजना का समवर्ती / मध्यावधि तृतीय पक्ष का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाएगा।

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय अन्तर्गत कृषक कल्याण संचालन समिति स्कीम के संचालन हेतु राज्य में पी.एम. किसान एवं केन्द्र स्तर पर पी.एम.यू को सहयोग करेगी। जिसमें विशिष्ट ज्ञान साझेदारी संस्थाएँ क्लस्टरों के चिन्हांकन, निर्यात क्लस्टरों का चिन्हांकन के साथ मांग एवं आपूर्ति में अंतर को दूर करने के लिए सप्लाइ चैन आधारित प्रोजेक्ट एक व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा।

14 निगरानी ढांचा

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियां प्रस्तावित योजना की वास्तविक समय पर निगरानी और प्रभावी फीड-बैक प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। संलग्नक- A के अनुसार समितियां बनाई जाएंगी।

इस वित्तपोषण सुविधा के तहत बनाई गई सभी संपत्तियां जियो टैग की जाएंगी। जिला निगरानी समिति और संबंधित ऋण देने वाली संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की जियो टैग की गई संपत्ति की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो।

15 प्रदाय एवं प्राप्त निगरानी फ्रेमवर्क (OOMF)

आउटपुट और आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) (अनुलग्नक-बी) निगरानी प्रणाली का एक हिस्सा होगा और परिणाम संकेतकों के माप को समय-समय पर DLMC, SLMC और NLMC द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।

16 पीएफएमएस के साथ संबंध

पीएफएमएस के माध्यम से बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों को ब्याज की छूट और ऋण गारंटी सपोर्ट जारी किया जाएगा।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा धन का वितरण आधार लिंकड बैंक खाते में होगा।

17 योग्य उधारकर्ता के चयन के लिए मानदंड

ऋण देने वाली संस्थाएँ नाबार्ड और निगरानी समितियों, पीएमयू के परामर्श से योग्य उधारकर्ता के चयन और परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए और एनपीए से बचने के लिए मानदंड तय करेंगी।

18 वीजीएफ की आवश्यकता

अगर वीजीएफ की आवश्यकता केंद्रीय / राज्य / स्थानीय निकायों द्वारा अनुमानित की जाती है, तो पीपीपी परियोजनाओं के लिए डीईए द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा।

19 सेक्टर विशिष्ट फोकस

कुल अनुदान का 24% योजना के तहत सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए (अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 8%)। इसके अलावा, उधार देने वाली संस्थाएं महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित उद्यमियों के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेंगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ समावेशी हो और इच्छित लाभार्थियों को प्राप्त हो।

20 राज्य विशिष्ट फोकस

राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन के कुल मूल्य के अनुपात के आधार पर वित्त पोषण की राज्य वार आवंटन सुविधा पर काम किया गया है जिसका एनेक्सचर- (सी) है।

निगरानी ढांचा

(i) राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी) की

संरचना: -

निम्नलिखित सदस्य और NLMC के अध्यक्ष होंगे: -

- a. सचिव (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार) (अध्यक्ष)
- b. एमडी एसएफएसी (लघु कृषक एग्री कन्सोर्टियम)
- c. एमडी, एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)
- d. विशेष सचिव / अतिरिक्त सचिव और एफए (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार)
- e. अतिरिक्त सचिव डी.एफ.एस. (संचालक वित्त सेवा)
- f. अतिरिक्त सचिव (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार)
- g. अध्यक्ष, नाबार्ड या उनके प्रतिनिधि
- h. प्रमुख सचिव-राज्य सरकार - रोटेशन द्वारा चार राज्य
- i. चार राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी (रोटेशन से)
- j. संयुक्त सचिव (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार) और किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य- सदस्य सचिव

कार्य: -

1. राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी) परियोजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन करेगी। यह परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी देगा।
2. राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन समिति (एनएलआईसी) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों की जांच और सिफारिश करेगी। यह राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी) द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित और समीक्षा करेगा।

(ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति संरचना: -

निम्नलिखित सदस्य और SLMC के अध्यक्ष होंगे: -

- a. मुख्य सचिव -अध्यक्ष
- b. कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रमुख सचिव कृषि
- c. प्रमुख सचिव (सहकारिता)

- d. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस)
- e. मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड
- f. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी
- g. राज्य द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं)।
- h. SLBC (राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी) आयोजक
- i. राज्य नोडल अधिकारी- सदस्य सचिव।

कार्य: -

1. राज्य स्तर की निगरानी समिति (SLMC) राज्य स्तर पर NIMC दिशानिर्देशों को लागू करेगी और NIMC को प्रतिक्रिया प्रदान करेगी।
2. यह राज्य में योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन भी करेगा।
3. यह DLMC के परामर्श से योजना में शामिल करने के लिए लाभार्थियों / परियोजनाओं की चयनित सूची की जांच और अनुमोदन भी करेगा।
4. यह OOMF प्रारूप के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करेगा और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेगा

(iii) जिला स्तरीय निगरानी समिति की संरचना: -

निम्नलिखित सदस्य और DLMC के अध्यक्ष होंगे: -

- a. जिला कलेक्टर - अध्यक्ष
- b. जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / सीडीओ- उपाध्यक्ष
- c. कृषि के जिला अधिकारी
- d. जिला पंजीयक सहकारिता
- e. राज्य द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं)
- f. एल.डी.एम (जिला स्तरीय बैंकर्स समिति)
- g. जिला प्रबंधक नाबार्ड- सदस्य सचिव

कार्य: -

1. जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) समग्र संरचना में कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली की पहली पंक्ति होगी।
2. यह लाभार्थियों की पहचान करेगा, परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा और पीएमयू के सहयोग से लाभार्थियों का समर्थन करने के लिए व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. यह प्रस्ताव की भी जांच करेगा और विचार के लिए SLMC को सिफारिश करेगा।

4. DLMC, OOMF प्रारूप के अनुसार SLMC के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित करेगा और PMU के समर्थन के साथ प्रगति की निगरानी करेगा।
5. DLMC, PMU के सहयोग से डैशबोर्ड को बनाए रखेगा।
6. यह योजना के सुचारू कार्यान्वयन और जिला स्तर पर किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए जिम्मेदार होगा। कार्यान्वयन के मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया में समिति को जहाँ भी आवश्यकता होगी जिला प्रशासन द्वारा समर्थित किया जाएगा।

OOMF फ्रेमवर्क

आउटपुट:

आउटपुट स्टेटमेंट	आउटपुट संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि अधोसंरचना का निर्माण आधुनिकीकरण एवं प्रोत्साहन	पात्र संस्थओं द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट संस्था		
	पात्र प्रोजेक्टों के लिए राशि का वितरण/विनियोग (करने में)		
ब्याज में छूट में वृद्धि एवं क्रेडिट गारंटी सहयोग उपलब्धता	में प्रदान की गई राशि ब्याज सबवेंशन		
	ब्याज में छूट प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की संख्या		
	ब्याज में छूट प्राप्त करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत (कुल प्रोजेक्टों में से) जिन्हे ऋण दिया गया		
	क्रेडिट गारंटी कवरेज में प्रदाय राशि (करोड़)		
	औसत प्रतिशत (कुल क्रेडिट गारंटी प्राप्त करने वालों में से)		

परिणाम:

आउटकम स्टेटमेंट	आउटकम संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि अधोसंरचना हेतु उपलब्ध संसाधनों उपयोग में वृद्धि	पूर्ण प्रोजेक्टों के लिए फण्ड का उपयोग		
	कृषि अधोसंरचना में अतिरिक्त निवेश का लाभ		
कृषि अधोसंरचना की क्षमता में वृद्धि	बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों के कारण कृषि क्षेत्र में कुल क्षमता वृद्धि (एमटी)		
	कटाई के बाद के नुकसान में कमी और खाद्य अपव्यय (%)		

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच वित्त पोषण सुविधा का टेंटेटिव आवंटन

क्र। नहीं।	राज्य	वित्तपोषण सुविधा INR करोड़
1	उत्तर प्रदेश	12831
2	राजस्थान Rajasthan	9015
3	महाराष्ट्र	8460
4	मध्य प्रदेश	7440
5	गुजरात	7282
6	पश्चिम बंगाल	7260
7	आंध्र प्रदेश	6540
8	तमिलनाडु	5990
9	पंजाब	4713
10	कर्नाटक	4525
11	बिहार	3980
12	हरियाणा	3900
13	तेलंगाना	3075
14	केरल	2520
15	ओडिशा	2500
16	असम	2050
17	छत्तीसगढ़	1990
18	झारखंड	1445
19	हिमाचल प्रदेश	925
20	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	900
21	उत्तराखंड	785
22	त्रिपुरा	360
23	अरुणाचल प्रदेश	290
24	नगालैंड	230
25	मणिपुर	200

26	मिजोरम	196
27	मेघालय	190
28	गोवा	110
29	दिल्ली	102
30	सिक्किम	56
31	पुडुचेरी	48
32	एक और एन द्वीप	40
33	दमन और दीव	22
34	लक्षद्वीप	1 1
35	दादरा और नगर हवेली	10
36	चंडीगढ़	9
	संपूर्ण	1,00,000



Agriculture Infrastructure Fund (AIF) as an Opportunity for Mandis

An agri-entrepreneurship led model to boost agri-infra development in Madhya Pradesh



**Farmer Welfare and Agricultural Development Department,
Government of Madhya Pradesh**

Agriculture Infrastructure Fund (AIF) launched to drive infra investment in Agri Infrastructure development

Key Take-away of the scheme



Size of the Fund:

Rs. 1 lakh Crore to be released as medium to long term debt financing facility



Scheme beneficiaries

PACS, FPOs, APMC, JLGs, SHGs Start-ups, agri entrepreneurs, Central/State agency or Local Body sponsored PPP Projects



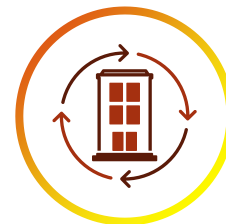
Scheme Period

13 Years
From FY20-21 to FY2032-33



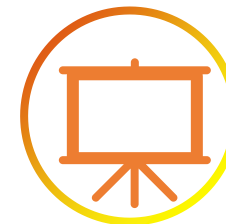
NABARD

will steer this initiative in association with the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare



Benefits

Interest Subvention, Credit Guarantee, Moratorium for repayment and speedy DPR sanction and loan disbursal



Eligible Projects

Post-harvest management and farm gate infrastructure projects

Agri Infra Fund (AIF) launched to setup post-harvest Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support

Key features of the scheme



3% interest subvention and credit guarantee coverage (under CGTMSE scheme)

upto Rs. 2 Crore (6 months to 2 years of moratorium)



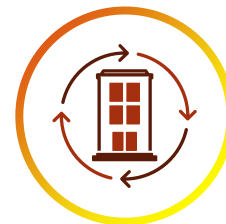
Convergence allowed to dovetail with all schemes (across ministries, state govt.)



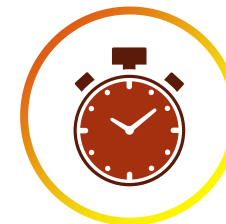
25 Commercial Banks, 40 Cooperative Banks, NABARD, etc. onboarded for priority sector lending under the scheme



Upfront interest subvention and cap on max. lending rate reducing cost of capital to ~5%



Loans available to farmers, FPOs, MSMEs, Agri entrepreneurs, agribusinesses, start-ups, state agencies, APMCs etc. with cap of 25 projects per beneficiary



MoA&FW driving speedy sanctions by working closely with lending institutions and State PMUs

Today, AIF offers a good opportunity for Agri-entrepreneurs & Start-ups to avail the benefits and scale up their business operations including export through establishing multiple projects under the scheme

Non-exhaustive

Core Post-harvest Management Infrastructure



Warehouses



**Assaying Labs/
weighingbridge**



Cold Storage



**Sorting &
Grading
Plants**



**Trading
Platforms**



**Drying
Yards**

Modern Value Addition Infrastructure



**Ripening
Chamers**



**Primary
Processing
Centres**



**Primary
Collection
Centres**



**Mills (Dal/
rice/
flour)**



**Irradiation
Plants**



**Solid Waste
Management**

Agriculture Infrastructure Fund: Madhya Pradesh

Multiple projects allowed under the scheme

Non-exhaustive

Storage Parks – Modern silos



Modern silos can **reduce wastage to less than 1%** and reduce desperate sell

Community farm assets (CHCs)



Mechanization can help **reduce costs/acre by ~30%**

Integrated pack-houses



Drive exports by meeting international standards and quarantine safety

IoT/ Precision farming assets



Promote AI based smart farming solutions – **can increase yield by 10% - 20%**

Cold chain infrastructure



Cold storages can **reduce post-harvest losses to less than 5%**

Organic inputs, Bio- stimulant prod. unit



Customized organic inputs and bio-fertilizers based on soil (**10%-20% premium**)

Refrigerated transportation



Ensure long distance fresh produce transfer; **wastage in transportation ~5%**

Community drying yards



Yards in every village - Can **reduce post-harvest losses by 5% to 10%**

Crop-wise PHM & primary processing activities covered under AIF (1/3)

Sr. No.	Crops	Eligible PHM & Processing Activities	Non-Eligible PHM & Processing Activities
1.	Cereals (Wheat, Paddy, etc.)	Cleaning, De-stoning, Sorting & grading, Hulling, Milling, Pounding, Grinding, Tempering, Parboiling, Soaking, Drying, Irradiation	Fermentation, Baking, Puffing, Flaking, Frying, Extrusion, Blending, Roasting
2.	Fruits and vegetables	Washing, Cleaning, Drying, Sorting Grading, Blanching for primary processing ,Cooling ,Waxing, Conditioning	Dehydration, Concentrated products Canning ,Juice extraction Sterilization
3.	Oilseeds	Cleaning, De-stoning, De-husking (decorticating machines) Winnowing Oil extraction (ghani, hydraulic press etc.	By-product utilization Refining Neutralization Bleaching

Crop-wise PHM & primary processing activities covered under AIF (2/3)

Sr. No.	Crops	Eligible PHM & Processing Activities	Non-Eligible PHM & Processing Activities
4.	Pulses	Cleaning ,De-stoning ,Drying ,Sorting & grading ,De-husking ,Splitting ,De-hulling ,Milling ,irradiation	Canning, Besan Papads, Pulse based foods, Puffed chickpea, Pulse polishing
5.	Cotton	Cleaning, Drying, Ginning, Pressing & Bailing, Lintering	Fibre finishing, Scouring ,Purifying ,Spinning ,Weaving
6.	Sugarcane	Cane unloading, Cleaning, Cane breaking, Cane milling ,Straining Evaporators, Centrifugation ,Storage tanks ,Dryers	

Crop-wise PHM & primary processing activities covered under AIF (3/3)

Sr. No.	Crops	Eligible PHM & Processing Activities	Non-Eligible PHM & Processing Activities
7.	Spices	Cleaning, Drying ,Sorting ,Boiling ,Polishing ,Grinding, Packaging, Storage, irradiation	Roasting, Sterilizing ,Thermal treatment
8.	Moringa	Washing, drying, milling ,storage Packaging	
9.	Herbal and Medicinal Crops	Cleaning, Sorting and drying	Syrup Pills, Cream Roasting, Frying, Distillation ,Concentration

Addition of bamboo sector projects under AIF except processing units for value addition of Bamboo

Eligible Activities:

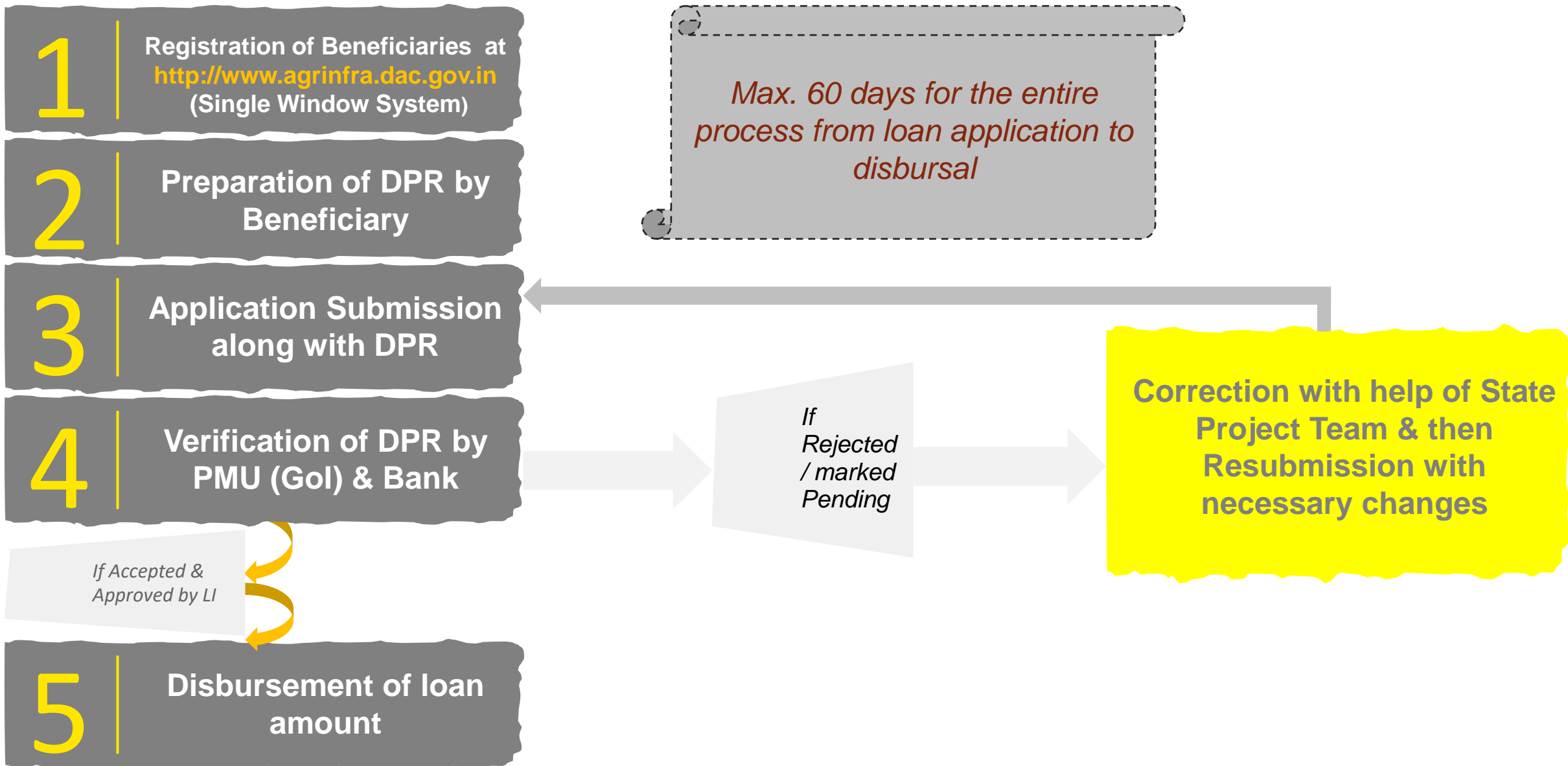
- ▶ Bamboo Treatment & Seasoning of Plants;
- ▶ Bamboo Depots and Godown;
- ▶ Bamboo Mandi (marketing place) & e-Trading;
- ▶ Rural Haat;
- ▶ Bamboo Bazaar;
- ▶ Common Facility Centre (CFC) etc.

Thank You

Govind Sharma (9098039381, 8800193376)

E mail- mpagriaif@gmail.com

A dedicated online portal setup for processing loan applications under AIF steps to avail AIF benefit





**Scheme Guidelines
for
CENTRAL SECTOR SCHEME
of
Financing facility under 'Agriculture Infrastructure Fund'**



Revised Scheme Guidelines

July 2021

**Department of Agriculture & Farmers Welfare
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India**

Index

S.No.	Particulars	Page No.
1	Introduction	3
2	Rationale of the Scheme	3-4
3	Objectives of Scheme	4-5
4	Implementation Period of Scheme	5
5.	Government Budgetary Support	5-6
6.	Eligible Projects	6-7
7.	Size of the financing facility& eligible beneficiaries	7
8.	Number of Projects per entity eligible under the scheme	7-8
9.	Participating institutions	8
10.	Refinance	9
11	Cap on lending rate	9
12.	Project Management and handholding support	9
13.	Convergence	10
14	Revisit of the Scheme	10
15	Monitoring framework	10
16	Output and outcome monitoring framework (OOMF)	10
17	Linkage with PFMS	10
18	Criteria for selection of eligible borrower	11
19	VGF requirement	11
20	Sector specific focus	11
21	States specific focus	11

Scheme Guidelines for CENTRAL SECTOR SCHEME of financing facility under 'Agriculture Infrastructure Fund'

1. Introduction

The role of infrastructure is crucial for agriculture development and for taking the production dynamics to the next level. It is only through the development of infrastructure, especially at the post-harvest stage that the produce can be optimally utilized with opportunity for value addition and fair deal for the farmers. Development of such infrastructure shall also address the vagaries of nature, the regional disparities, development of human resource and realization of full potential of our limited land resource.

In view of above, the Hon'ble Finance Minister announced on 15.05.2020 ₹ 1 lakh crore Agri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers. Financing facility of ₹ 1,00,000 crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points Primary Agricultural Cooperative Societies, Farmers Producer Organizations, Agriculture entrepreneurs, Start-ups, etc. Impetus for development of farm-gate & aggregation point, affordable and financially viable Post Harvest Management infrastructure.

Accordingly, DA&FW has formulated the Central Sector Scheme to mobilize a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects relating to post-harvest management Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support.

Subsequently, in the budget announcement made on 01.02.2021, it was decided to extend the benefit of the scheme to APMCs. Accordingly, modifications in the scheme were carried out with the approval of Cabinet to make it more inclusive.

2 Rationale of the Scheme

Agriculture and allied activities are the primary income source for ~58% of total population of India. ~85% of the farmers are Small Holding Farmers (SHFs) with less than 2 hectares of land under cultivation and manage ~45% of agricultural land. Annual income of majority of the farmers is very low. Further, India has limited infrastructure connecting farmers

to markets and hence, 15-20% of yield is wasted which is relatively higher vs. other countries where it ranges between 5-15%. Investment in agriculture in India has further been stagnant with less than 2% CAGR over last 5 years. Investment in FY17 was ~ ₹ 2.19 lac crore out of which private sector share was ~83% vs. a higher investment of ~ ₹ 2.50 lac crore in FY14 and a higher share of private sector at ~88%. Also, lack of investor confidence is leading to lower plowback ratio (~14% of Gross Value addition in FY18) vs. other sectors (~33% of Gross Value addition in FY18).

3 Objectives of the Scheme

To mobilize a medium - long term debt finances facility for investment in viable projects for post-harvest management Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support in order to improve agriculture infrastructure in the country. This financing facility will have numerous objective for all the stakeholders in the agriculture eco-system.

- a. Farmers (including FPOs, PACS, Marketing Cooperative Societies, Multipurpose cooperative societies, State Agencies, Agricultural Produce Market Committees (Mandis), National & State Federations of Cooperatives, Federations of FPOs and Federations of Self Help Groups (SHGs). etc.).
 - Improved marketing infrastructure to allow farmers to sell directly to a larger base of consumers and hence, increase value realization for the farmers. This will improve the overall income of farmers.
 - With investments in logistics infrastructure, farmers will be able to sell in the market with reduced post-harvest losses and a smaller number of intermediaries. This further will make farmers independent and improve access to market.
 - With modern packaging and cold storage system access, farmers will be able to further decide when to sell in the market and improve realization.
 - Community farming assets for improved productivity and optimization of inputs will result in substantial savings to farmers.
- b. Government
 - Government will be able to direct priority sector lending in the currently unviable projects by supporting through interest subvention, incentive and credit guarantee. This will initiate the cycle of innovation and private sector investment in agriculture.

- Due to improvements in post-harvest infrastructure, government will further be able to reduce national food wastage percentage thereby enable agriculture sector to become competitive with current global levels.
- Central/State Government Agencies or local bodies will be able to structure viable their own or PPP projects for attracting investment in agriculture infrastructure.

c. Agri entrepreneurs and startups

- With a dedicated source of funding, entrepreneurs will push for innovation in agriculture sector by leveraging new age technologies including IoT, AI, etc.
- It will also connect the players in ecosystem and hence, improve avenues for collaboration between entrepreneurs and farmers.

d. Banking ecosystem

- With Credit Guarantee, incentive and interest subvention lending institutions will be able to lend with a lower risk. This scheme will help to enlarge their customer base and diversification of portfolio.
- Refinance facility will enable larger role for cooperative banks and RRBs.

e. Consumers

- With reduced inefficiencies in post-harvest ecosystem, key benefit for consumers will be a larger share of produce reaching the market and hence, better quality and prices. Overall, the investment via the financing facility in agriculture infrastructure will benefit all the eco-system players.

4 Implementation Period of Scheme

The Scheme will be operational from 2020-21 to 2032-33. Loan disbursement under the scheme will complete in six years. During the financial year 2020-21, the projects amounting to about ₹ 4000 crore have been sanctioned under the scheme. The financing facility of the balance amount of ₹ 96,000 crore will be distributed @ ₹16,000 crore for 2021-22 and @ ₹ 20,000 crore per year for the next four years w.e.f. 2022-23 to 2025- 26. Repayment period covered under the financing facility will be for a maximum period of 7 years including the moratorium period of up to 2 years.

5 Government Budgetary Support

Budgetary support will be provided for interest subvention and credit guarantee fee as also administrative cost of PMU. The details are as below:-

Sl. No.	Name of Component	Norms
1	Interest Subvention Cost	All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of ₹ 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. In case of loans beyond ₹ 2 crore, then interest subvention will be limited up to ₹ 2 crore. The extent and percentage of funding to private entrepreneurs out of the total financing facility may be fixed by the National Monitoring Committee.
2	Credit Guarantee Cost	Credit guarantee coverage will be available for eligible borrowers from this financing facility under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme for a loan up to ₹ 2 crore. The fee for this coverage will be paid by the Government. In case of FPOs the credit guarantee may be availed from the facility created under FPO promotion scheme of DA&FW.
3	Administration Cost of PMU	Farmers Welfare Programme Implementation Society under DACFW will provide PMU support to the scheme at the central level and state PMUs of PM KISAN at state level. Services of knowledge partners will be engaged to identify clusters including export clusters and gaps in supply chains to target projects and prepare viable project reports to support the beneficiaries.

6 Eligible Projects

The scheme will facilitate setting up and modernization of key elements of the value chain including

(A) Post Harvest Management Projects like:

- (i) Supply chain services including e-marketing platforms
- (ii) Warehouses
- (iii) Silos
- (iv) Pack houses
- (v) Assaying units
- (vi) Sorting & grading units
- (vii) Cold chains
- (viii) Logistics facilities
- (ix) Primary processing centers
- (x) Ripening Chambers

(B) Viable projects for building community farming assets including –

- (i) Organic inputs production
- (ii) Bio stimulant production units
- (iii) Infrastructure for smart and precision agriculture.
- (iv) Projects identified for providing supply chain infrastructure for clusters of crops including export clusters.
- (v) Projects promoted by Central/State/Local Governments or their agencies under PPP for building community farming assets or post-harvest management projects.

Further, an indicative list of crop wise eligible and ineligible post-harvest/ primary processing activities under the scheme is given in **Annexure-A**

Note: Digital Connectivity and optic fiber infrastructure shall be eligible investment as part of development of the aforementioned eligible projects.

7 Size of the financing facility and eligible beneficiaries

₹ 1 Lakh Crore to be provided by banks and financial institutions as loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Marketing Cooperative Societies, Farmer Producers Organizations (FPOs), Self Help Group (SHG), Farmers, Joint Liability Groups (JLG), Multipurpose Cooperative Societies, Agri-entrepreneurs, Startups and Central/State agency or

Local Body sponsored Public Private Partnership Projects, State Agencies, Agricultural Produce Market Committees (Mandis), National & State Federations of Cooperatives, Federations of FPOs (Farmer Produce Organizations) and Federations of Self Help Groups (SHGs). APMCs operating regulated markets for agriculture and allied sector produce including fisheries shall also be eligible.

PACS who have adopted digitization for handling its operations will be given preference under this scheme.

8 Number of Projects per entity eligible under the scheme

Interest subvention for a loan upto ₹ 2 crore in one location is eligible under the scheme. In case, one eligible entity puts up projects in different locations then all such projects will be eligible under the scheme for loan upto ₹ 2 crore. However, for a private sector entity, such as farmer, agri entrepreneur, start-up there will be a limit of maximum of 25 such projects. This limitation of 25 projects will not be applicable to state agencies, national and state federations of cooperatives, federations of FPOs and federation of SHGs. Location will mean physical boundary of a village or town having a distinct LGD (Local Government Directory) code. Each of such project should be in a location having a separate LGD (Local Government Directory) Code.

APMCs will be eligible for multiple projects (of different infrastructure types) within their designated market area. In such cases, interest subvention for a loan upto ₹ 2 Crore will be provided for each project of different infrastructure types e.g. cold storage, sorting, grading and assaying units, silos, etc. within the designated market area of the APMC.

9 Participating institutions

All scheduled commercial banks scheduled cooperative banks, Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) may participate to provide this financing facility, after signing of Memorandum of Understanding (MoU) with National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)/DA&FW.

10 Refinance

If required, need based refinance support will be made available by NABARD to all eligible lending entities including cooperative banks and RRBs as per its policy.

11 Cap on lending rate

Lending rate of participating lending entities will be decided after due consultation with lending entities and same will be circulated to all stake holders. Lending institutions will sign MOU with DA&FW/ NABARD for implementation of the Scheme. MOUs to be signed by DA&FW/NABARD with banks/financial institutions with a view that DA&FW/NABARD will negotiate cap on lending rates in a fair manner.

12 Project Management and handholding support

An online platform will be made available in collaboration with participating lending institutions to provide information and loan sanctioning facility. Agri Infra fund will be managed and monitored through an online MIS platform. It will enable all the qualified entities to apply for loan under the fund. The system will also provide benefits such as transparency of interest rates offered by multiple banks, scheme details including interest subvention and credit guarantee offered, minimum documentation, faster approval process as also integration with other scheme benefits. At the back end, the platform will also provide multiple views of dashboards across district; state and national level PMUs to monitor the total sanctioned amount and number of borrowers, total interest subvention benefit availed, loan statement summary, demographic and geographic mix of borrowers and type of projects.

Farmers Welfare Programme Implementation Society under DACFW will provide PMU support to the scheme at the central level and state PMUs of PM KISAN at state level. Services of knowledge partners will be engaged to identify clusters including export clusters and gaps in supply chains to target projects and prepare viable project reports to support the beneficiaries.

Project reports with indicative unit costs will be prepared by Central and State PMUs for guidance of beneficiaries and lending entities. Such project reports shall be available on online platform.

13 Convergence

Any grant or subsidy available under any present or future scheme of Central/State

government can be availed for projects under this financing facility. In cases of capital subsidy such amount shall be considered as promoter's contribution. However, a minimum of 10% of the project cost shall be mandatory as promoter's contribution.

14 Revisit of the Scheme

The scheme will be re-visited by Department of Expenditure after disbursement of ₹ 20,000 crore is completed, for evaluation and midcourse correction if required. Concurrent/mid-term third party independent evaluation of the scheme in addition to end- line evaluation will be conducted as and when required.

15 Monitoring framework

The National, State and District Level Monitoring Committees to ensure real-time monitoring and effective feed-back about the implementation of the proposed scheme. The Committees will be set up as per **Annexure-B**.

All assets created under this financing facility shall be geo tagged. The District Monitoring Committee and respective lending entity shall ensure that updated information on such geo tagged assets is available on the online portal.

16 OUTPUT AND OUTCOME MONITORING FRAMEWORK (OOMF)

The Output and Outcome Monitoring Framework (OOMF) (**Annexure-C**) will be a part of monitoring system and the measurement of outcome indicators will be monitored periodically by DLMC, SLMC and NLMC.

17 Linkage with PFMS

Interest subvention and credit guarantee support will be released to Banks and lending institutions through PFMS.

Disbursal of funds by lending entities to beneficiaries under this scheme shall be in Aadhaar linked bank account.

18 Criteria for selection of Eligible Borrower

Lending institutions will decide criteria for selection of eligible borrower in consultation with NABARD and monitoring committees, PMUs and keeping in mind the viability of the projects and to avoid NPA.

19 VGF Requirement

In case VGF requirement is projected by central / state / local bodies, norms as prescribed by DEA for PPP projects will be adhered to.

20 Sector specific focus

24% of total grants – in – aid under the scheme should be utilized for SC/ST entrepreneurs (16% for SC and 8% for ST). Besides this, lending institutions would ensure adequate coverage of entrepreneurs belonging to women and other weaker segments of society may be provided loan on priority basis to ensure that benefits of implementation are inclusive and accrued to the intended beneficiaries in accordance with Government guidelines and policies.

21 State specific focus

Tentative State wise allocation of financing facility has been worked out on the basis of the ratio of total value of output of Agriculture and Allied sectors of States/UTs and placed at **Annexure- D**

Crop-wise eligible PHM & Primary Processing Activities

Sl. No.	Crops	Eligible PHM & Primary Processing Activities	Not eligible under AIF
1	Cereals (Wheat, Paddy, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • De-stoning • Sorting & grading • Hulling • Milling • Pounding • Grinding • Tempering • Parboiling • Soaking • Drying • Sieving • Irradiation 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermentation • Baking • Puffing • Flaking • Frying • Extrusion • Blending • Roasting
2	Fruits and vegetables	<ul style="list-style-type: none"> • Washing • Cleaning • Drying • Sorting • Grading • Blanching for primary processing • Cooling • Waxing • Conditioning 	<ul style="list-style-type: none"> • Dehydration • Concentrated products • Canning • Juice extraction • Sterilization
3	Oilseeds	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • De-stoning • De-husking (decorticating machines) • Winnowing • Oil extraction (ghani, hydraulic press etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • By-product utilization • Refining • Neutralization • Bleaching
4	Pulses	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • De-stoning • Drying • Sorting & grading • De-husking • Splitting • De-hulling • Milling • Irradiation 	<ul style="list-style-type: none"> • Canning • Besan • Papads • Pulse based foods • Puffed chickpea • Pulse polishing
5	Cotton	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning 	<ul style="list-style-type: none"> • Fibre finishing

Sl. No.	Crops	Eligible PHM & Primary Processing Activities	Not eligible under AIF
		<ul style="list-style-type: none"> • Drying • Ginning • Pressing & Bailing • Lintering 	<ul style="list-style-type: none"> • Scouring • Purifying • Spinning • Weaving
6	Sugarcane	<ul style="list-style-type: none"> • Cane unloading • Cleaning • Cane breaking • Cane milling • Straining • Evaporators • Centrifugation • Storage tanks • Dryers 	
7	Spices	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • Drying • Sorting • Boiling • Polishing • Grinding • Packaging • Storage • Irradiation 	<ul style="list-style-type: none"> • Roasting • Sterilizing • Thermal treatment
8	Cocoa	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • Gathering of pods • Sorting • Breaking of pods • Fermentation of cocoa • Drying • Storage 	<ul style="list-style-type: none"> • Roasting • Winnowing • Alkalization
9	Coffee	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • Drying of cherries • Washing • Hulling • Pulping 	<ul style="list-style-type: none"> • Roasting • Grinding • Extraction
10	Jute	<ul style="list-style-type: none"> • Cutting • Retting • Stripping • Washing • Drying • Bailing • Packing • Storage 	

Sl. No.	Crops	Eligible PHM & Primary Processing Activities	Not eligible under AIF
11	Cashew	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • Streaming in boiler • Shell cutting • Drying • Peeling • Grading • Packaging 	
12	Moringa	<ul style="list-style-type: none"> • Washing • Drying • Milling • Storage • Packaging 	
13	Tea	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • Withering • Rolling • Fermentation • Drying • Sorting 	
14	Rubber	<ul style="list-style-type: none"> • Mastication • Mixing • Shaping • Curing • Irradiation 	
15	Herbal and Medicinal Crops	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning • Sorting • Drying 	<ul style="list-style-type: none"> • Syrup • Pills • Cream • Roasting • Frying • Distillation • Concentration

Monitoring framework

(i) National level Monitoring Committee (NLMC)

Composition :-

Following will be the Members and Chairman of the NLMC:-

- a. Secretary (DA&FW) (Chairman)
- b. MD SFAC
- c. MD, NCDC
- d. Special Secretary/Additional Secretary and FA (DA&FW)
- e. Additional Secretary DFS
- f. Additional Secretary (DA&FW, GoI)
- g. Chairman, NABARD or his representative
- h. Principal Secretary-State Government (s)- Four States by rotation
- i. State Nodal Officers of four States (by rotation)
- j. Joint Secretary (DA&FW) and CEO of Farmers Welfare Programme Implementation Society- Member Secretary

Functions:-

1. National level Monitoring Committee (NLMC) will guide and steer the implementation of the scheme. It will approve the guidelines for implementation of the scheme.
2. National level Implementation Committee (NLIC) will examine and recommend the guidelines for implementation of the scheme. It also will ensure and review the implementation of the scheme as per approved guidelines by the National level Monitoring Committee (NLMC)

(ii) State level Monitoring Committee

Composition:-

Following will be Members and Chairman of the SLMC :-

- a. Chief Secretary –Chairman
- b. Agriculture Production Commissioner/Principal Secretary Agriculture
- c. Principal Secretary (Cooperation)
- d. Registrar of Cooperative Societies (RCS)
- e. Chief General Manager (CGM), NABARD
- f. Regional Director, NCDC

- g. Officers nominated by State (not more than three).
- h. SLBC Convener.
- i. State Nodal Officer- Member Secretary.

Functions:-

1. State level Monitoring Committee (SLMC) will implement the NIMC guidelines at the state level and provide feedback to NIMC.
2. It will also guide and steer the implementation of the scheme in the state.
3. It will set the targets as per OOMF format and review the progress regularly

(iii) District Level Monitoring Committee

Composition:-

Following will be Members and Chairman of the DLMC:-

- a. District Collector – Chairman
- b. Chief Executive Officer of District Panchayat/CDO- Vice Chairman
- c. District Officer of Agriculture
- d. District Registrar Officers nominated Cooperative Societies
- e. Officers nominated by State (not more than three)
- f. Lead District Manager of DLBC
- g. District Manager NABARD- Member Secretary

Functions:-

1. District level Monitoring Committee (DLMC) The DLMC will be the first line of implementation and monitoring system within the overall framework.
2. DLMC will set targets in consultation with SLMC as per OOMF format and monitor the progress closely with the support of PMU.
3. DLMC will maintain the Dashboard in collaboration with PMU.
4. It will be responsible for the smooth implementation of the scheme and resolve any issues at the district level. In the process of sorting out implementation issues the Committee would be supported by the district administration wherever required.

OOMF Framework

OUTPUTS:

Output statement	Output Indicators	Target	Achievement
Promoting creation and modernization of agriculture infrastructure	No. of projects submitted by eligible entities		
	Disbursement of funds for eligible projects/investments (₹ Crore)		
Increase in amount of interest subvention and credit guarantee support provided	Amount outgo on account of interest subvention (₹ Crore)		
	No. of projects receiving interest subvention		
	Percent projects receiving interest subvention (of the total projects offered loan under the scheme)		
	Amount outgo on credit guarantee coverage (₹ Crore)		
	Average percent credit guarantee coverage of the total credit extension under the scheme.		

OUTCOMES:

Outcome Statement	Outcome Indicators	Target	Achievement
Improvement in resource provision for agriculture infrastructure	Percentage of fund utilized for completed projects		
	Additional investments leveraged due to agriculture infrastructure fund interventions (₹ Crore)		
Enhancement in agriculture infrastructure capacity	Total capacity addition in agriculture sector due to infrastructure activities funded (MT)		
	Reduction in post-harvest losses and food wastages (%)		

Tentative Allocation of Financing Facility among States/UTs

Sl. No.	State	Financing Facility INR Crore
1	Uttar Pradesh	12831
2	Rajasthan	9015
3	Maharashtra	8460
4	Madhya Pradesh	7440
5	Gujarat	7282
6	West Bengal	7260
7	Andhra Pradesh	6540
8	Tamil Nadu	5990
9	Punjab	4713
10	Karnataka	4525
11	Bihar	3980
12	Haryana	3900
13	Telangana	3075
14	Kerala	2520
15	Odisha	2500
16	Assam	2050
17	Chhattisgarh	1990
18	Jharkhand	1445
19	Himachal Pradesh	925
20	Jammu & Kashmir & Ladakh	900
21	Uttarakhand	785
22	Tripura	360
23	Arunachal Pradesh	290
24	Nagaland	230
25	Manipur	200

Sl. No.	State	Financing Facility INR Crore
26	Mizoram	196
27	Meghalaya	190
28	Goa	110
29	Delhi	102
30	Sikkim	56
31	Puducherry	48
32	A & N Islands	40
33	Daman & Diu	22
34	Lakshadweep	11
35	Dadra & Nagar Haveli	10
36	Chandigarh	9
	Total	1,00,000